न्यायालय संख्या - 48

प्रकरण: - रिट - बी संख्या - 4142/2023

याचिकाकर्ता: - सुदामा

प्रतिवादी: - उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: - ओंकार नाथ राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: - सी.एस.सी.

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान की धारा 226 के अंतर्गत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश जोत एवं चकबंदी अधिनियम की धारा 11 (1) के अंतर्गत अपील संख्या 201154054400008 (सुदामा बनाम रामप्रीत और अन्य) के शीघ्र निस्तारण का अनुरोध किया गया है, जो चकबंदी के सहायक बंदोबस्त अधिकारी, पडरौना, जनपद कुशीनगर के न्यायालय में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता ने 03.08.2004 को एक विलम्बित अपील योजित की है, जिसमें उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 9 (क) (2) के अंतर्गत कार्यवाही में चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.1982 को निरस्त किया गया है। हालांकि, इसके योजित होने की तिथि से यह अतिविलंबित है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस मामले में कोई आपत्ति नहीं है यदि इस न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्धारित अवधि के भीतर पूर्वोक्त अपील के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किया जाता है।

5. इस परिदृश्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका को सहायक बंदोबस्त अधिकारी, पडरौना, जिला कुशीनगर (प्रतिवादी संख्या 2), जिसके समक्ष उपर्युक्त मामला लंबित है, को निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले की योग्यता पर कोई टिप्पणी किए

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated version. Not for Legal Use.

बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः बारह माह की अवधि के भीतर, शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए।

6. यह उम्मीद की जाती है कि किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, विधि के अनुसार एक तर्कपूर्ण और सकारण आदेश द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

7. पूर्वोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

आदेश दिनांक: - 2.1.2024/वीकेजी

Translated version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"